

ब्राजील की तर्ज पर संचालन से उबरेगा चीनी उद्योग

- किसान विज्ञान समागम में पुरानी बीमारू प्रजातियों के स्थान पर हाई सुक्रोज की बुआई पर जोर
- केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने किसानों की दुर्दशा के लिए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया



मोदीपुरम : भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में किसान विज्ञान समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, किसानों और वैज्ञानिकों ने गन्ना किसानों की समस्याओं पर मंथन किया। विचार-विमर्श में यह निष्कर्ष निकला कि किसान गन्ने की बुआई का रकबा पच्चीस प्रतिशत कम कर और उच्च सुक्रोज वाले गन्ने की फसल का उत्पादन करें तो काफी हद तक चीनी उद्योग पर मंडरा रहे संकट से निपटा जा सकता है।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दूर-दूर से आए गन्ना किसानों के लिए नवीनतम किस्मों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने किसानों की दुर्दशा के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया।

स्टालों का निरीक्षण करते केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डा. संजीव बालियान व कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि।

किसान विज्ञान समागम में मिल प्रतिनिधियों ने चीनी के कम रेट और गन्ने की गिरती क्वालिटी के चलते कम होते चीनी उत्पादन का रोना रोया। सिभावली चीनी मिल से आरएस सहरावत, मवाना से वेदपाल और नंगलामल से एलडी शर्मा ने चीनी उद्योग की दिक्कतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने न्यूनतम चीनी मूल्य के निर्धारण की बात कही।

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के मुख्य गन्ना सलाहकार जेपी सिंह ने ब्राजील की तर्ज पर चीनी मिलों के संचालन की बात कही। आयोजक गन्ना अनुसंधान संस्थान के डा. ओपी सिन्हा ने कहा कि किसानों द्वारा बोई जा रही पुरानी

प्रजातियां बीमार हो चुकी हैं। उन्होंने को नई विकसित प्रजातियां 0238, को0118, कोएलके 9709 को उगाने की बात कही। बालियान ने कहा कि कहा कि सौ करोड़ रुपये वेस्ट यूथ

के 22 जिलों के किसानों को जागरूक करने के लिए दिए गए थे, जिसमें अभी तक साठ लाख खर्च किए गए।

आईआईएफएसआर के निदेशक चो

मिल मालिकों को संरक्षण दे रही प्रदेश सरकार : बालियान

मोदीपुरम : प्रदेश सरकार किसानों का बकाया हड़पने वाले चीनी मिल मालिकों को जेल भेजने की बजाए उन्हें संरक्षण दे रही है। शुक्रवार को यह बात केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने प्रेसवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को भुगतान कराने में नाकामयाब रही है। 600 करोड़ रुपये गत सीजन का बकाया है। वहीं इस सीजन में भी चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तरह इस बार भी चीनी बैव कर किसानों को दी जाने वाली धनराशि का डायवर्जन कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि चीनी मिल मालिक विदेशों में पेश कर रहे हैं और गन्ना किसान आर्थिक बहहली झेल रहे हैं। ऐसे मिल मालिकों को जेल भेजना चाहिए।

• किसानों के छह सौ करोड़ बकाया

कई चीनी मिल मालिक स्वयं को दिवालिया घोषित कर किसानों की रकम हड़पना चाह रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में उन्होंने किसानों को पाटी बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार मिल मालिकों के खिलाफ सख्ती करती तो कब का किसानों का भुगतान हो गया होता। उन्होंने कहा कि मवाना, तितहरी, नंगलामल, मोदीनगर और मलकपुर चीनी मिल ने किसानों के छह सौ करोड़ रुपये का डायवर्जन कर दिया। यह जांच का विषय है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पर कुछ मामले की जांच कानून के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार जांच कराने में अक्षम है तो सीबीआई से जांच कराए।

गंगवार ने वैज्ञानिक खोजों को किसानों तक पहुंचाने की बात कही। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एनएस गोड ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर किसानों ने भी अपनी समस्याएं बताईं।

कागजों पर नहीं खेतों पर दिखे

वैज्ञानिकों का कार्य : कृषि राज्य मंत्री डा. संजीव कुमार बालियान ने कहा कि वैज्ञानिकों की बड़ी फौज गन्ने के विकास के लिए कार्य कर रही है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा। अगर वैज्ञानिकों का कार्य जब तक खेतों पर नहीं दिखेगा तब तक उनका प्रोन्नति नहीं की जाएगी।

जागरण